



1. द्वीप प्रशासन ने धन्नीखाड़ी बांध सहित मुख्य जल स्रोतों में गिरते जल स्तर को देखते हुए परामर्श जारी किया है।
2. पर्यावरण एवं वन विभाग, की ओर से कल से दो दिवसीय मैंग्रोव कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
3. अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से जाँच प्रक्रियाओं और कानूनी जागरूकता पर संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया।
4. जहाजरानी सेवा निदेशालय ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए जहाजों के यात्रा कार्यक्रम की समय सारणी जारी की है।



अंडमान निकोबार प्रशासन ने धन्नीखाड़ी बांध सहित मुख्य जल स्रोतों में पानी के गिरते स्तर को देखते हुए यहां के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। प्रशासन ने नागरिकों से पानी का किफायती उपयोग करने का आग्रह किया है। इस वर्ष उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान बहुत कम बारिश हुई है। धन्नीखाड़ी क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में यह सबसे कम दर्ज की गई वर्षा है। प्रशासन ने पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पिछले दो वर्षों में 20.36 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ कई परियोजनाएं शुरू की है। अगले वर्ष के लिए 30.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है ताकि जल संकट से निपटा जा सके। प्रशासन ने कहीं भी पाइपलाइन में रिसाव या बर्बादी दिखने पर तुरंत सहायता केंद्र, अंडमान लोक निर्माण विभाग और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के पास सूचित करने को कहा है।



पर्यावरण एवं वन विभाग, की ओर से कल और 22 मार्च को मेगापोड रिजॉर्ट में सुबह नौ बजे से दो दिवसीय मैंग्रोव कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, वन अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों को मैंग्रोव संरक्षण के आधुनिक रुझानों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में तटीय सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता, पारिस्थितिकी पर्यटन, मैंग्रोव वनों को फिर से उगाने की तकनीकें और स्थानीय लोगों की भागीदारी और मैंग्रोव से जुड़े आजीविका के



अधिकारियों ने भाग लिया। सत्र का नेतृत्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सचिव सम्राट रॉय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-II जयंत मुखर्जी और दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता के. सुगधन ने किया। उन्होंने महत्वपूर्ण कानूनों और उनके बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की, जिनमें पॉक्सो अधिनियम, NDPS अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और जाँच प्रक्रिया शामिल हैं। न्यायाधीशों ने जाँच और अदालती कार्यवाही के दौरान आने वाली सामान्य चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए।

<><><><><><><><>

जहाजरानी सेवा निदेशालय ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए जहाजों के यात्रा कार्यक्रम की समय सारणी जारी की है। एम वी स्वराज द्वीप 25 अप्रैल से विशाखापत्तनम और चेन्नई के लिए नियमित सेवाएं प्रदान करेगा। मई माह में एम वी नालंदा चेन्नई और कोलकाता के लिए, जबकि जून माह में एमवी कैंपबेल बे की सेवाएं ली जाएगी। टिकटों की बुकिंग की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। यात्री विभाग के ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या स्टार्टस टिकटिंग काउंटर से टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे।

<><><><><><><><>

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान 'नई चेतना 2.0' के तहत मदर टेरेसा विलेज ऑर्गनाइजेशन ने सामुदायिक स्रोत अधिकारियों और सीडी ब्लॉक फरारगंज के सहयोग से कल होपटाउन में लैंगिक भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर होपटाउन प्रधान रशीदा बीबी, सरकारी अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, ग्रामीण और स्कूली छात्र शामिल हुए। नई चेतना 2.0 का उद्देश्य महिलाओं और लैंगिक रूप से विविध व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना है। सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के स्रोत अधिकारियों ने नशीली पदार्थों के दुरुपयोग, पॉक्सो और पॉस अधिनियम और घरेलू हिंसा विरुद्ध कानूनी प्रावधानों पर जानकारी दी। प्रधान रशीदा बीबी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए इस आयोजन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

<><><><><><><><>

बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, रंगत द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आंगनवाड़ी-सह-क्रेच कार्यकर्ताओं के पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियों की घोषणा की गई है। रंगत क्षेत्र के लिए 25 मार्च सुबह दस बजे प्रमुख पंचायत समिति कार्यालय, और मायाबंदर के लिए 27 मार्च पंचायत

समिति प्रमुख के कार्यालय, में ली जाएगी। उम्मीदवारों की सूची संबंधित ग्राम पंचायतों और समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जारी की गई है।

<><><><><><><><>

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स के पदों के लिए आज वॉक-इन इंटरव्यू रखा गया है। साक्षात्कार सुबह साढ़े दस बजे सचिवालय के लघु सम्मेलन कक्ष में आयोजित होगा। उम्मीदवारों से अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुबह साढ़े नौ बजे तक उपस्थित रहने को कहा गया है। अधिक जानकारी निदेशालय के पोर्टल या प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

<><><><><><><><>